# भारत के वनक्षेत्र में 5 फीसदी की बढ़ोतरी : मनमोहन

**नई दिल्ली** (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि देश के वनक्षेत्र में पांच फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने जो यह जानकारी दी है वह पर्यावरणविद को खुश कर सकता है। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के सरोकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में मिल जुलकर काम करने की इच्छा शक्ति के अभाव पर गहरी चिंता जताई है लेकिन कहा है कि भारत इस मामले के समानतापरक समाधान के लिए अपनी ओर से सकारात्मक भूमिका निभाने को प्रतिबद्ध है। डॉ.सिंह ने सतत विकास पर 12 वीं शिखर बैठक के उद्घाटन सत्र में कहा कि देश में 1997 से 2007 के दौरान वन क्षेत्र में पांच फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश की इस उपलब्धि पर उन्हें प्रसन्नता हो रही है। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि वनाच्छादन में बढ़ोतरी के बाद से इसमें हल्की गिरावट का रुझान भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लेकिन यह भी कहा कि ग्रीन इंडिया मिशन के करीब 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनाच्छादन सघन बनाने के लक्ष्य के साथ भारत हर वर्ष 5-6 करोड़ टन कार्बन डाईआक्साइड को निस्तेज करने और वार्षिक उत्सर्जन में छह प्रतिशत तक

■ जलवायु परिवर्तन पर सहयोग के अभाव पर चिंता जताई

की कटौती करने में कामयाब होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता और इन खतरों से निबटने की जवाबदेही का बंटवारा देश विशेष में उत्सर्जन के अनुपात में तथा विकास की उसकी खास जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

फिनलैंड की राष्ट्रपति तारजा हालोनेन को 2012 के लिए सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार प्रदान करने के बाद प्रधानमंत्री ने जवाबदेहियों की समानतापरक साझेदारी की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि विकास शील देशों की तुलना में विकसित देशों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन दस से 12 गुणा तक अधिक है और उत्सर्जन में कटौती की जवाबदेही भी इसी अनुपात में होनी चाहिए।

इसके अलावा जरूरी यह भी है कि समस्या का ऐसा समाधान ढूंढ़ा जाए कि विकास एवं प्रगति के अधिकार से विकासशील देश वंचित नहीं हों। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाती है तो भारत अपनी जवाबदेही उठाने में कतई पीछे नहीं रहेगा। इस संदर्भ में भारत की भूमिका की चर्चा करते हुए डॉ.सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना कर रहे एक प्रमुख विकासशील देश की हैसियत से इस समस्या के सफल, नियम आधारित, समानतापरक एवं बहुपक्षीय समाधान की तलाश में भारत की गंभीर दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत व्यवस्था, यूएनएफ सीसीसी ने इसका एक उपयुक्त आधार भी दे दिया है और भारत इन आधारों पर वार्ता को आगे बढ़ाने में सकारातमक भूमिका निभाने को प्रतिबद्ध है।

डॉ. सिंह ने बाघों की गणना के इस वर्ष के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2006 की तुलना में बाघों की आबादी 20 प्रतिशत के इजाफे के साथ 1700 तक पहुंच गई है और आशा जताई कि बाघ संरक्षण के उपायों से सीख लेकर अन्य लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के भी उपाय किए जा सकेंगे।